

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2507] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 5, 2018/आषाढ़ 14, 1940 No. 2507] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 2018/ASHADHA 14, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2018

का.आ. 3261(अ).— केन्द्र सरकार, न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण एवं अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें), नियमावली, 2017 के नियम 4 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 22 ई द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.06.2018 के पत्राचार संख्या 9/14/2018-ई.ओ.(एस.एम. II), द्वारा संसूचित मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन से एतद्वारा श्री दिनेश सिंह को, एन.सी.डी.आर.सी. के सदस्यों की नियुक्ति से सम्बन्धित मामले, अर्थात् रिट याचिका संख्या 1129/2017 सहित, वित्त अधिनियम, 2017 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में लिम्बत न्यायालय के मामलों के अध्यधीन, दिनांक 01/07/2018 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अविध के लिए अथवा उनके 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.) के सदस्य (गैर न्यायिक) के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. जे-1/5/2016-सी.पी.यू.(खंड 6)]

अमित मेहता. संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2018

S.O. 3261(E).— In exercise of the powers conferred by Section 22E of the Consumer Protection Act, 1986 read with rule 4 of the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 2017 and with the approval of the Appointments Committee of the Cabinet (ACC), conveyed by Department of Personnel and Training vide communication No. 9/14/2018 –EO (SM II) dated 14.06.2018, the Central Government hereby appoints Sh. Dinesh Singh as

3800 GI/2018 (1)

Member (Non-Judicial) in the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) w.e.f. 01/07/2018 (F/N) for a period of five years with effect from the date of assumption of the charge, or till attaining the age of 70 years, or until further orders, whichever is the earliest, subject to outcome of the court cases challenging the provisions of the Finance Act, 2017 and the rules notified thereunder pending before the Supreme Court , including the case relating to appointment of Members in NCDRC i.e. WP No. 1129/2017.

[F. No. J-1/5/2016- CPU (Part 6)]
AMIT MEHTA, Jt. Secy.